

जाना आवश्यक है)। (ख) विहित प्रपत्र में आधार कार्ड तथा बैंक खाता संख्या का संग्रहण (आधार कार्ड तथा बैंक खाता का प्रथम पृष्ठ जिसपर खाता संख्या लिखा हो का छायाप्रति) किया जाना।		Verification staff.
5. सत्यापन के पश्चात् अयोग्य पाये गये लाभार्थियों के राशन कार्ड को अनुभंडल स्तर पर अभियान चलाकर रद्द करने की कार्रवाई किया जाना।	दिनांक 30.07.2016 से 31.08.2016 तक	S.D.O & M.O
6. जिला द्वारा e-pds portal पर जन वितरण प्रणाली दुकान (FPS) का अद्यतन करते हुए शुद्धिकरण किया जाय।	दिनांक 18.06.2016 से 29.06.2016 तक	D.S.O & D.I.O
7. विभाग द्वारा चयनित भंडर के माध्यम से जिला स्तर पर संग्रहित प्रपत्र से - (क) डाटा संग्रहण के उपरांत प्रपत्र में भरी गई प्रविष्टियों का मिलान संलग्न छायाप्रति के साथ किये जाने का कार्य। (ख) डाटा का अद्यतन एवं आधार, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, मोबाईल नं० आदि का प्रविष्टि का कार्य। प्रविष्टि के समय विहित प्रपत्र को स्कैन कर सॉफ्ट कॉपी में save कर फाईल बना लिया जाय। (ग) प्रविष्टि कार्य के उपरांत check list print कराकर मूल संग्रहित प्रपत्र से मिलान प्रखंड स्तरीय कर्मियों द्वारा किया जाना। (घ) मिलान के उपरांत पाये गये अशुद्धियों को भंडर द्वारा पुनः Software के माध्यम से अद्यतन किया जाना।	दिनांक 30.07.2016 से 13.09.2016 तक	नामित एजेसी M.O, B.S.O प्रखंड स्तरीय कर्मियों
8. संग्रहित आधार संख्या का Authentication का कार्य चयनित एजेसी या अन्य माध्यम से कराते हुए डाटा बेस में गलत अथवा सही आधार संख्या, बैंक खाता संख्या को चिन्हित करते हुए राशन कार्ड संख्या से Mapping किया जाना।	दिनांक 14.09.2016 से 21.09.2016 तक	

उपरोक्त अवधि विस्तार में निम्नलिखित कार्रवाई करते हुए संलग्न विहित प्रपत्र I से IV तक में प्रतिवेदन संकलित की जाय :-

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सुयोग्य लाभुक बचे होने की सूचना प्राप्त हो रही है। उसके संदर्भ में निदेश दिया जाता है कि वैसे बचे हुए लाभुकों से RAPS के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किया जाय एवं नियमानुसार जांचोपरांत चयन करने की कार्रवाई करते हुए राशन कार्ड निर्गत करने की कार्रवाई की जाय।
2. जांच दल के गठन में पंचायत सचिव/हल्का कर्मचारी/टोला सेवक/विकास मित्र/आंगनवाड़ी सेविका/किसान सलाहकार इत्यादि कर्मियों की सेवा ली जा सकती है। गठित जांच दल के कार्यों का अनुश्रवण हेतु पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों को भी लगाया जाय।
3. प्रपत्र की छपाई जिलों के लिए निर्धारित चुनाव दर या अन्य कोई दर यदि पूर्व से जिलों में निर्धारित हो तो, वित्तीय नियमावली का अनुपालन करते हुए करायी जा सकती है। प्रपत्र छपाई के लिए राशि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है।
4. तकनीकी सहयोग जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 देंगे।
5. डाटा सत्यापन हेतु प्रिंट कराये गये राजस्व ग्रामवार पंजी को डाटा सत्यापन कराने के पश्चात् डाटा तैयार करने हेतु संबंधित प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को Co-ordinator (समन्वयक) बनाया जाय। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि वे डाटा सत्यापन के पश्चात् ग्रामवार पंजियों को प्राप्त कर सत्यापनोपरांत डाटा को विभागीय प्रपत्र I और II में संकलित कर प्रतिवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराएँ।
6. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सत्यापनोपरांत ग्रामवार प्राप्त डाटा पंजी को उपलब्ध कराये गये विभागीय अलमीरा में सुरक्षित रखेंगे तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के आदेश से ग्रामवार

